

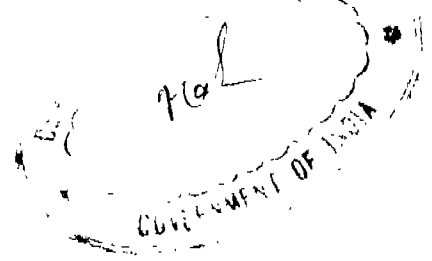


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 104]
No. 104]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1999/अग्रहायण 15, 1921
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1999/AGRAHAYANA 15, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1999

फा. सं. टीएएमपी/86/99-विविध.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण संलग्न आदेशानुसार सभी प्रमुख पत्तन न्यासों के दरों के मान में परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों और "पोतवणिक स्वामित्व वाले से भिन्न कंटेनरों" के संबंध में समय सीमा निर्धारित करता है।

मामला संख्या टीएएमपी/86/99-विविध

आदेश

(नवम्बर, 99 के 10वें दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने भूमि किराया वसूल करने के लिए परित्याग किए गए कंटेनरों के संबंध में 2 महीने की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करते हुए 5 सितंबर, 99 को एक आदेश पारित किया था और चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के वर्तमान दरों के मान में एक नई टिप्पणी शामिल की थी। जेएनपीटी के सीएफएस के लिए प्रशुल्कों का अनुमोदन करते हुए इस प्राधिकरण ने परित्याग किए गए कंटेनरों के मामले में भूमि किराया की उपर्युक्त समय सीमा निर्धारित की थी। प्राधिकरण की यह उल्लिखित स्थिति रही है कि पोत-आगमन के पश्चात् कार्गो हटाने/निकासी करने की 45/60 दिन की सांविधिक सीमा का पालन किया जाएगा और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तब परेषिती की लागत पर कार्गो की नीलामी की जाएगी।

2. सीएचपीटी और जेएनपीटी के मामले में निर्धारित समय सीमा सांविधिक सिद्धांत लागू करने से संबंधित है और ऐसे प्रशुल्कों को शासित करने के लिए बनाए गए विषय से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार भी है। इसलिए, यह निर्णय किया गया है कि इस समय सीमा को सभी महापत्तन न्यासों द्वारा "साझा तौर पर अपनाने" के लिए लागू किया जाए।

3. इस समय परित्याग किए गए कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार लागू करने से छूट देने के लिए महापत्तनों के दरों के मान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तदनुसार, यह प्राधिकरण परित्याग किए गए कंटेनरों के संबंध में 2 महीने की समय सीमा निर्धारित करता है और सभी प्रमुख पत्तन न्यासों के दरों के मान में निम्नलिखित टिप्पणियां शामिल करता है:—

(i) परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवाणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों के संबंध में भंडारण प्रभार ऐसे परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवाणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों के संबंध में कंटेनर के आगमन की तारीख से 2 महीने अथवा बंदरगाह कार्यालय में ऐसे परित्याग की लिखित में सूचना की प्राप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक सीमित किए जाएंगे।

परित्याग की सूचना के बंदरगाह कार्यालय में लिखित में प्राप्त होते ही यातायात प्रबंधक तत्काल यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर को भंडारण क्षेत्र से हटाए जाने के लिए और बिना समय गंवाए इसे खाली करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(ii) 'पोतवाणिक स्वामित्व वाले कंटेनर' से भिन्न कंटेनर को मुख्य लाइन ऑपरेटरों(एमएलओ) की लागत और जिम्मेदारी पर पत्तन न्यास द्वारा नियमित भंडारण क्षेत्र से हटाया जाएगा और बिक्री वेयरहाउस/ओवरफ्लो शेडों में रखा जाएगा तथा उसके बाद एमएलओ द्वारा न्यास परिसर से खाली कंटेनरों को हटाए जाने से पहले उन कंटेनरों को खाली किया जाएगा।

4. सभी महापत्तन न्यासों को अपने दरों के मान में उपर्युक्त प्रावधानों को तदनुसार शामिल करने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1999

E. No. TAMP/86/99-Misc.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby prescribes time limit of two months for abandoned FCL Containers/Shipper owned containers and 'other than shipper owned containers' in all the Major Port Trusts Scale of Rates as in the Order appended hereto.

CASE NO. TAMP/86/99-MISC.

ORDER

(Passed on this 10th day of November 99)

This Authority had passed an order on 5 September 99 prescribing a maximum time limit of two months in respect of abandoned containers for charging ground rent and introduced a new note in the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT). While approving the tariffs for the JNPT's CFS also this Authority

had prescribed the above time limit for charge of ground rent in case of abandoned containers. It has been the stated position of the Authority that the statutory limit of 45 / 60 days for de-stuffing / clearing after landing the cargo shall be adhered to; and, if it is not adhered to, then, the cargo shall be auctioned at the consignee's cost.

2. The time limit prescribed in the case of the CHPT and the JNPT amounts only to an application of the statutory principle and is also in accordance with the Guideline on the subject developed to govern such tariffs. It has, therefore, been decided to extend this time limit for 'common adoption' by all the Major Port Trusts.

3. At present there is no specific provision in the Scale of Rates of the Major Ports to exempt levy of storage charges for abandoned containers. Accordingly, the Authority fixes a time limit of two months in respect of abandoned containers and introduces the following Notes in the Scales of Rates of all the Major Port Trusts :-

- (i). Storage charges on abandoned FCL Containers / Shipper owned containers shall be limited upto the date of receipt of intimation of abandonment in the Harbour Office in writing or two months from the date of landing of the container whichever is earlier, for such abandoned FCL Containers / Shipper owned containers.

Immediately on receipt of the intimation of abandonment in the Harbour Office in writing, the Traffic Manager shall ensure that steps are taken at once to facilitate removal of the container from the Storage Area and for destuffing it without any loss of time.

- (ii). The container other than 'shipper owned container' shall be removed from the regular Storage area and moved to Sales Warehouse / Overflow Sheds by the Port Trust at the cost and responsibility of the Main Line Operators (MLOs); and, thereafter, the container can be destuffed before the empty containers are removed from the Trust's premises by the MLOs.

4. All the Major Port Trusts are hereby directed to include the above provisions accordingly in their Scale of Rates.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/Exty./143/99]

